कृषि : उभरते मुद्दे और संभावित दृष्टिकोण *

वाइ.वी. रेड्डी

यह मेरे लिये सौभाग्य की बात है कि मैं इस यादगार अवसर पर आप के साथ उपस्थित हूँ। निस्संदेह रूप से यह एक उपाधि वितरण समारोह के अवसर पर दिया जाने वाला भाषण है किन्तु यह आचार्य एन.जी.रंगा गारू की याद में अपना भाषण समर्पित करने का भी एक अवसर है। राजनैतिक अर्थव्यवस्था और कृषि के संबंध में उनके दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक हो गये हैं तथा आज के खाद्यान्नों की ऊंची कीमतों के कारण हलचल भरे आज के विश्व और किसानों की भलाई पर अपना ध्यान केंद्रित करने से इसका विशेष महत्व हो गया है। मेरे नौजवान दोस्तो आप को भारत और विश्व दोनों ही स्तरों पर कृषि से संबंधित उभरते मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

आचार्य एन.जी. रंगा ने, जिनकी शिक्षा इंग्लैण्ड की प्रतिष्ठित संस्थाओं में हुई थी और जो मद्रास विश्वविद्यालय के पचइयप्पा महाविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, ने वैधानिक निकायों में पचास वर्ष की सेवा करनेवाले संसदीय व्यक्ति के रूप में गिनीज़ बुक आफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। वह राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्रता सेनानी थे और खेती-किसानी करनेवाले मजदूरों के महत्व को विचारार्थ आगे बढ़ानेवाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति थे। उनके विश्वास ने ही उन्हें भारत कृषिकर लोक पार्टी तथा राजाजी के साथ मिलकर स्वतंत्र पार्टी की स्थापना के लिये प्रेरित किया जिसने परमिट-लाइसेन्स राज के विरुद्ध अपने कड़े तेवर दिखाये। 1991 से भारत में हुए आर्थिक सुधारों ने हमें अच्छी सेवाएं दी हैं और इन्होंने अनेक प्रकार से प्रोफेसर रंगा के सुझावों में से एक नामतः 'उदारीकरण' का अनुसरण किया है। तथापि, हमने हाल ही में खेती-किसानी करनेवाले मजदूरों के महत्व को स्वीकार करना शुरू किया है जिसे दशकों पहले उन्होंने मान्यता दी थी। हमें अब जाकर महसूस हुआ है कि संपूर्ण विश्व में सभी

* डॉ. वाइ. वी. रेड्डी, गवर्नर, भारिबैंक द्वारा 5 जून 2008 को दिया गया आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद का 50वां दीक्षांत भाषण।

वर्गों के लोगों के लिये कृषि विशेषकर खाद्यान्नों के मूल्यों के संबंध में स्थिति कितनी जटिल हो गयी है। वास्तव में,मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के संदर्भ में पूरे विश्व के केंद्रीय बैंकों के मौजूदा एजेंडे में यह सबसे ऊपर है। मेरा विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित संकाय और ज्ञानी छात्र प्रो.रंगा के विचारों की समसामयिक प्रासांगिकता को समझेंगे और आज हमारे सामने जो मुद्दे हैं उन्हें हल करने में ऐतिहासिक भूमिका अदा करने के लिए वचनबद्ध रहेंगे।

सर्वप्रथम, 2008 में स्नातक की पदवी पानेवाले क्लास को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं जो बड़े परिश्रम से अर्जित की गई अपनी डिग्रियां और पुरस्कार प्राप्त करेंगे। मैं उन स्टाफ सदस्यों को, जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हैं तथा समस्त संकाय को शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने एवं हमारी युवा पीढ़ी के व्यक्तित्व को संवारने के अच्छे मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि छात्रों और स्टाफ का ही यह प्रयास है जिसने इस कृषि विश्वविद्यालय को आइसीएआर के सबसे बढ़िया संस्थान का पुरस्कार एक के बाद एक जल्दी-जल्दी दो बार जीतने और साथ ही विगत कुछ वर्षों में आइसीएआर ऑल इंडिया कंपिटीटिव एक्ज़ामिनेशन में दो बार छात्रों का आइसीएआर सर्वोत्तम कार्य पुरस्कार जीतने में सहायता की है।

प्रिय नये स्नातक पदवीधारको, जिन विषयों में आपको प्रशिक्षित किया गया है उनमें रिज़र्व बैंक की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। हमारे मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखने और उत्पादन करने की प्रक्रिया तथा रोज़गार पैदा करने की प्रक्रिया में सहायता करने से संबंधित है। हमारे देश में लगभग एक बिलियन लोगों के घरेलू बज़टों के लिए कृषि से संबंधित जिंसों के मूल्य वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। भारत में हमारे काम करने वाले लोगों की आबादी का लगभग साठ प्रतिशत कृषि और संबंधित गतिविधियों सरकारों और विश्व विद्यालयों, जैसे कि आप का है, के कार्यक्षेत्र में आते हैं, रिज़र्व बैंक को इन गतिविधियों की निगरानी करनी पड़ती है और वित्तीय प्रणाली के माध्यम से विशेषकर मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता वित्तीय समावेशन और ऋण वितरण के अर्थ में जन नीति का समर्थन करना पड़ता है। इस पृष्ठभूमि में, हालांकि कृषि से संबंधित बहुत से मुद्दे हैं लेकिन कुछ मुद्दों तक ही सीमित रहूंगा। मैं खाद्यान्न की गंभीर समस्या पर संक्षेप में चर्चा करूंगा जिससे आज विश्व जूझ रहा है। इसके बाद भारतीय स्थिति का वर्णन करुंगा, विशेष रूप से, कृषि के प्रति रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण का।

खाद्यान्नों के मूल्य वैश्विक मुद्दे के रूप में

हाल के महीनों में खाद्यान्नों के मूल्य में वैश्विक रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए जहां वैश्विक खाद्यान्न मूल्य सूचकांक कैलेंडर वर्ष 2006 में औसतन 10.5 प्रतिशत तथा 2007 में 15.2 प्रतिशत बढ़ा। इसमें पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में वर्ष 2008 के पहले चार महीनों में 40.8 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई। खाद्यान्न और कृषि संगठन के अनुसार विश्व के 37 देशों में इस समय खाद्यान्न संकट महसूस किया जा रहा है। उनमें से 31 अफ्रीका और एशिया में हैं। पिछले साल (मई के अंत में) विश्व बैंक ने बढ़ते खाद्यान्न मूल्यों के गरीबों पर होनेवाले प्रभाव से लड़ने में सहायता देने के लिए 1.2 बिलियन अमरीकी डालर की द्रुतगामी निधीयन सुविधा का अनावरण किया। इस समय (रोम में 3-5 जून) विश्व के अग्रणी देश खाद्यान्न और कृषि संगठन (एफएओ) की मेजवानी में आयोजित विश्व खाद्यान्न सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का रहे हैं। यह सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब खाद्यान्नों के मूल्यों में पिछले बारह महीनों में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस शिखर सम्मेलन के कार्य विवरण में शामिल हैं फसलोत्पादन व्यापार, सहायता बढ़ाने से संबंधित

मुद्दे, जैव-ईंधनों की ओर विपथन तथा कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन का समग्र प्रयोजन प्रयोजन बढ़ते खाद्यान्न मूल्यों के सामने खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का निवारण तथा मौसम परिवर्तन और दीर्घावधिक में विश्व खाद्यान्न सुरक्षा के प्रति सावधानियां बरतने के लिए नीतियों, रणनीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करके इस खाद्यान्न संकट का तात्कालिक, अल्पावधिक तथा चिरस्थायी हल निकालना है।

निस्संदेह रूप से मौजूदा वैश्विक खद्यान्न स्थिति बहुत गंभीर है और इसलिए हमें अल्पावधि में ही खाद्यान्न मूल्यों में हुई ऐसी नाटकीय वृद्धि के कारणों को समझना होगा।

पहला, यह कहा गया है कि चीन और भारत की तेजी से हो रही वृद्धि हर वर्ष लाखों लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा रही है और इस प्रकार वैश्विक मांग पर जबर्दस्त दबाव बना रही है। यह भी तर्क दिया गया है कि खाद्यान्न बास्केट बदल गई है और यह मांग बढ़ने में योगदान दे रही है। तथापि, बारीक संवीक्षा से पता चलेगा कि बढ़ी हुई मांग एक वर्ष में मूल्यों में अचानक उछाल की व्याख्या नहीं कर सकती क्योंकि ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं यदि दो दशक से ज्यादा नहीं तो एक दशक से भी ज्यादा समय से चढ़े हुए और तेज स्तरों पर बढ़ रही हैं। इसके अलावा, चीन शुद्धतः गेहूं निर्यातक देश रहा है और इसका प्रति व्यक्ति मांस उपभोग 2005 तक पश्चिम मानकों तक पहुंच गया है। वनस्पति खाद्य तेलों के संबंध में जहां हाल के वर्षों में भारत लगातार शुद्धतः आयातक रहा है और साथ ही दालों के मामले में भी कुछ हद तक आयातक रहा है, को छोड़कर तो भारत निर्यातक अथवा आयातक के रूप में एक मार्जिन में है।

दूसरा, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन जैसे कुछ देशों में सूखे की स्थितियां मूल्यवृद्धियों का कुछ स्पष्टीकरण दे सकती हैं। यह भी संभव है कि अनेक देशों में घटते जा रहे भंडारों के स्तरों ने भी कमी की स्थितियों में भी वृद्धि की हो। इसके अलावा कुछ देशों में खाद्य उत्पादों के निर्यातों पर प्रतिबंध लगाने या हतोत्साहित करने के प्रशासनिक उपायों से उन देशों में मूल्यों में स्थिरता आई हो लेकिन इसकी वजह से कुछ अन्य देशों में कीमतें बढ़ गयी हों। तथापि, ये कारण पूरी तरह से एक साथ सभी पण्यों की कीमतों में हो रही विश्वव्यापी वृद्धियों को पूरी तरह से स्पष्ट करने में असमर्थ हैं।

तीसरा, यह तर्क दिया जाता है कि ऊर्जा लागतों में हो रही वृद्धि के परिणामस्वरूप मूल्य प्रणित मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई है किन्तु कृषि की समग्र लागतों में ऊर्जा लागतों का योगदान खाद्यान्न मूल्यों की भारी वृद्धियों को स्पष्ट नहीं कर सकता।

चौथा, मौजूदा बढ़े हुए ऊर्जा मूल्यों के बारे में यह है कि मक्के और खाद्य तेलों का जैव-ईंधनों की दिशा में विपथन हुआ है जो नीतिगत निर्णयों द्वारा काफी प्रभावित हैं। एकदम स्पष्ट रूप से जैव-ईंधनों की दिशा में यह विपथन एक नीति प्रेरित नयी वास्तविकता है जो उन उत्पादों में हो रही मूल्य वृद्धि के साथ-साथ है और इसीलिए यह ध्यान देने योग्य बात है।

पांचवां, हो सकता है पण्य व्यापार के वित्तीयकरण तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों में मौजूदा असाधारण परिस्थितियों ने मूल्यों में इस उछाल को प्रभावित किया हो। अमरीका में ब्याज दरों में हाल ही में की गयी कटौती तथा प्रणाली में डाली गयी चलनिधि के परिणामस्वरूप वित्तीय बाजारों में आए तूफान और खजानों के घटते लाभों के परिप्रेक्ष्य में निवेश पण्य बाजार जैसे नए रास्ते तलाश रहे हैं। अपेक्षाकृत आसान चलनिधि और कम ब्याज दरें अपने आप में ही इन्वेंट्रियों की धारिता को आकर्षक बना देती हैं और इस प्रकार पण्य बाजारों में

ज्यादा अस्थिरता पैदा करते हैं। अमरीकी डॉलर के कमजोर होने को भी खाद्यान्न मदों सहित पण्य बाजारों में आई हाल ही की अस्थिरता को एक कारण माना जा सकता है। यह स्पष्ट है कि यह घटना अब सभी स्तरों पर खाद्यान्नों के मूल्यों में हो रही वृद्धि के साथ ही घट रही है।

संक्षेप में, जहां खाद्यान्नों के मूल्यों में मांग और आपूर्ति पक्ष दबाव हैं वही इस बाद के भी विचारणीय तर्क है कि खाद्यान्न मूल्यों में हाल ही में हुई अभूतपूर्व वृद्धियां विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऊंची ऊर्जा लागतों और वित्तीय बाजारों तथा वित्तीय संस्थाओं की हलचल के प्रति जननीति प्रतिक्रियों के साथ निकट से जुड़ी हुई हैं। कहां जाता है कि ऐसे समय में खाद्यान्नों का जैव-ईंधनों की दिशा में नीति प्रेरित विपथन का प्रभाव महत्वपूर्ण है तथा यह दर्शाता है कि लोगों के खाली पेट भरने के बजाय गाड़ियों के ईंधन टैंकों को भरने को प्राथमिकता दी जा रही हैं, इसी प्रकार, कभी-कभी यह माना जाता है कि जननीति स्थिरता को दिए गए भारांक अब वास्तविक क्षेत्र - विशेषकर संवेदनशील पण्यों जैसे कि खाद्यान्न में स्थिरता के व्यय पर हो सकते हैं। उसी समय, यह एक आम राय है कि पूरे विश्व में बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्यान्नों से संबंधित जननीति में किसानों को खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिए है ताकि मध्यावधि में बढ़ती मांग को आसानी से पूरा किया जा सके।

जहां तक निकट भविष्य में संभावनाओं की बात है, ढेर सारे ऐसे कठिन तत्व हैं खासकर तेल के भावी मूल्यों के पथ, वित्तीय बाजारों विशेषकर करेंसी बाजारों में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में हुई प्रगति और अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी की सीमा और समग्र रूप में वैश्विक अर्थव्यस्था पर इसके परिणामी प्रभाव से संबंधित तत्व जिन्हें मापना कठिन है। इसके अलावा, खाद्यान्न विशेषकर जैव-ईंधन की दिशा में विपथन; सीमापारीय व्यापार; सब्सिडियां और अतिरिक्त भंडारों का पुनर्भरण अथवा उपयोग से संबंधित जननीति वैश्विक रूप से मूल्यों के बढ़ने को प्रभावित करेगी। तथापि, इससे छुटकारा पाने का पहलू यह है कि खाद्यान्नों के संबंध में आपूर्तिकारी प्रतिक्रिया एक या दो वर्ष में संभव है। एफएओ अनुमानों के अनुसार, यद्यपि भंडारों के बहुत खाली हो जाने के बावजूद 2008 में गेहूँ का उत्पादन एक नया रिकार्ड स्थापित करेगा। 2008 में वैश्विक रूप से चावल का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से बेहतर रहेगा और इस प्रकार रखे गए भंडारों में से थोड़ा बहुत खाली हो जाने की संभावना है। ऐसी संभावना है कि मौजूदा वर्ष में खाद्य तेलों के वैश्विक उत्पादन में लगभग 3 प्रतिशत की गिरावट आयेगी और एफएओ के अनुसार, प्रत्याशा है कि तिलहनों और खाद्य तेलों के मूल्य स्थिर बने रहेंगे।

वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न मूल्यों के लिए मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि की संभावनाएं क्या हैं? ओईसीडी और एफएओ के कृषि संबंधी भावी परिदृश्य के अनुसार जहां कृषि पण्यों के मूल्य हाल ही के अपने रिकार्ड ऊँचाई से कम होंगे वही यह भी प्रत्याशा है कि वे पिछले दशक के माध्य स्तर से औसतन काफी ऊपर रहेंगे। एफएओ द्वारा आयोजित विश्व खाद्य सुरक्षा पर कुछ स्तरीय सम्मेलन में भाषण देते हुए दो दिन पहले (3 जून को) संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा था कि विश्व का खाद्यान्न उत्पादन 2030 तक 50 प्रतिशत और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

हमारे लिए वैश्विक खेती उत्पादन और मूल्यों के ऐसे परिदृश्य के निहितार्थ एकदम स्पष्ट होने चाहिए। हमारे देश में तेज आर्थिक वृद्धि के साथ खाद्यान्न उपभोग अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा क्योंकि हम लोग की संख्या एक बिलियन से अधिक है। खाद्यान्न बास्केट भी बदलेगी।

हमें देश के भीतर ही खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ानी होगी क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में घरेलू आपूर्ति में सीमांत आवश्यकताओं अथवा यहां तक कि कमी के बोध का भी वैश्विक कीमतों पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। चूंकि हमारे यहां का आधे से अधिक काम करने वाले लोगों की संख्या खेती पर निर्भर करती है और चूंकि हमारे पास उत्पादकता बढ़ाने की काफी संभावना है। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं की हम कम से कम अपने देश के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित न कर सकें। वास्तव में भारत विश्व के लिए 'अन्नपूर्णा' बन सकता है और मैं महसूस करता हूँ कि आंध्र प्रदेश भारत के लिए 'अन्नपूर्णा' बन सकता है।

इस संबंध में, हमारे प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकों में से एक डॉ.एम.एस. स्वामिनाथन का उद्धरण देने से बेहतर कार्य मैं नहीं कर सकता, "भारत के पास एक ऐसी तकनीकी और आर्थिक क्षमता है जो यह दिखा सकती है कि विभिन्न मौसम पैटर्न के अनुसार खेती को किस प्रकार समायोजित किया जा सकता है। आशा की जाती है कि रोम का यह सम्मेलन भारतीय प्रतिनिधियों के लिए निराशा के इस महासमुद्र के बीच एक चमकती हुई मशाल के रूप में काम करेगा"।

भारतीय स्थिति

अब हमें भारतीय स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सर्वप्रथम, यह स्वीकार किया जाना चाहिए की हाल के महीनों में भारत में खाद्यान्नों के मूल्य में हुई वृद्धि अनेक देशों में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत थोड़ी है। विशेष रूप से जनवरी और अप्रैल 2008 के बीच गेहूं और चावल की वैश्विक कीमतें लगभग दुगुनी हो गई हैं, जबकि भारत में यह वृद्धि उस वृद्धि की तुलना में दसवें हिस्से से भी रही है। तात्पर्य यह है कि यह हमारे देश में खाद्यान्न सुरक्षा की डिग्री पर जोर देने की चिरस्थायी जननीति का समर्थन है, विशेषकर आबादी के काफी बड़े हिस्से की संवेदनशीलता के कारण। इसके बावजूद भी 2006 और 2007 में भी भारत में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में अचानक उछाल आया है। उस अवधि के दौरान खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) सूचकांक में औसत वार्षिक वृद्धि लगभग 7.0 प्रतिशत थी। खाद्यान्न मूल्यों में हुई वृद्धि में 2006 के दौरान गेहूं (13.0 प्रतिशत) सबसे आगे था जिसमें 2007 की मूल्य वृद्धि में चावल (6.0 प्रतिशत) और खाद्य तेल (13.1 प्रतिशत) भी आकर जुड़ गये । तथापि, 2008 के दौरान खाद्यान्न मूल्यों में कुछ नरमी दिखाई दी। पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि (3.1 प्रतिशत) की तुलना में 2008-09 (17 मई 2008 तक) के दौरान खाद्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में लगभग 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ज्यादा रुचि की बात अलग-अलग वस्तुओं के लिये वर्तमान संभावनाएं हो सकती है जो सरकारी खरीद में महत्वपूर्ण सुधार के साथ गेहूं के लिए सकारात्मक प्रतीत होती हैं। चावल उत्पादन के संबंध में जो नब्बे के दशक के मध्य से थोड़ा रुक सा गया था, 2005-06 से इसमें कुछ विपरीत रुख दिखाई दिया है। 2006-07 में खाद्य तेल के मूल्यों में तेज वृद्धि हुई और 2007-08 के दौरान इसमें अचानक वृद्धि हुई है। तथापि, मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अब तक कुछ नरमी देखी गई है। दालों में उत्पादन के रुके हुए स्तरों के कारण मांग-आपूर्ति का अंतर आयात से पूरा किया गया है। लेकिन घरेलू कीमतों में पिछले एक वर्ष के दौरान गिरावट देखने के पहले अचानक उछाल देखा गया था। चीनी की संभावनाएं, जिनमें से भारत बड़े उत्पादकों में से एक है, मौजूदा वर्ष के लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं क्योंकि 2005-06 से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

कुल मिलाकर वैश्विक मूल्यों में कुछ कमी बेहतर घरेलू आपूर्तियों का संकेत और हमारे अतिरिक्त भंडारों में वृद्धि है और आपूर्ति की दिशा में सरकार द्वारा पहले ही किये गए उपायों की शृंखला के साथ आशा की जाती है कि आनेवाले महीनों में इसके परिणाम दिखाई देंगे। तथापि, मध्यावधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो लगभग 2 वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था, के सकारात्मक परिणाम आने चाहिए।

कृषि के प्रति रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

रिज़र्व बैंक के प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता और वृद्धि की गति बनाए रखना है, विशेषकर रोजगार सृजन करते रहना है। इस प्रयास में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि हमारे देश में मूल्य सूचकांकों में कृषि पण्यों को अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण भारांक दिया जाता है और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर लगाम लगाने में भी इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। रोजगार के अर्थ में भी कृषि का वर्चस्व है। कुल रोजगार में कृषि का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत है जबकि जीडीपी के अर्थ में इसका हिस्सा उसके एक तिहाई से भी कम है। तथापि, रिज़र्व बैंक ने दिया गया नीतिगत स्थान मूलतः मुद्रा आपूर्ति, ब्याज और विनिमय दरों में वृद्धि तथा कुछ हद तक बैंकों के माध्यम से ऋण प्रवाह के संबंध में उचित दृष्टिकोण के माध्यम से सकल मांग के प्रबंधन तक सीमित है। तथापि, कृषि के महत्व को देखते हुए रिज़र्व बैंक कृषि के प्रति अपना दृष्टिकोण वार्षिक रिपोर्टों द्वारा निर्मित करता है। मुझे इसको संक्षेप में बताने दें, हाल के वर्षों में रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्टों - पिछले पांच वर्षों में रिज़र्व बैंक के निदेशकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार और विश्लेषण।

क) 1990 के दशक के मध्य से कृषि क्षेत्र में वृद्धि न सिर्फ कम रही बल्कि इसमें काफी विचलन भी रहा। हाल के वर्षों में फसल यील्ड में अस्थिरता रही है। चिंता का जो विषय रहा है वह अच्छे मानसून वर्षों के होते हुए भी कुछ कुछ जगहों पर लगातार सूखा पड़ने की घटनाओं का होना। हाल के वर्षों में खाद्य उपभोक्ता बास्केट में विविधता देखी जा रही है जिसके अंतर्गत मूल्यवर्धित खाद्य उत्पाद जैसे मांस, पौल्ट्री, मछली, तरकारी- भाजी और फल सम्मिलित हुए हैं। उपभोग में आए इस बदलाव के प्रति उत्पादन में भी बदलाव का होना आवश्यक है।

ख) वास्तविक अर्थों में कुल सकल पूंजी निर्माण में कृषि का हिस्सा हाल के वर्षों में सरकारी निवेश के हिस्से में निरंतर जारी क्षरण के कारण गिरता जा रहा है। कृषि की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने में निजी निवेश की अपर्याप्तता के कारण ग्रामीण आधारभूत संरचना की दशा पर चिंताएं उठ खड़ी हुई है, जो वृद्धि के रास्ते में बड़ी रुकावट डाल सकती है।

ग) हाल के वर्षों में कृषि ऋण सुपुर्दगी मैकेनिज़म में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। तथापि कृषि को मिलनेवाले ऋण के प्रवाह में कुछ रुकावटें अभी भी है। कृषि में उच्च वृद्धि हासिल करने के लिए वित्तीय क्षेत्र में अन्य बातों के साथ-साथ जिन क्षेत्रों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है वे हैं - फसल नुकसान के लिए बीमा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाएं । कौशल नयन करने तथा सोच बदलने के साथ-साथ ऋण मूल्यांकन और जोखिम प्रबंध प्रणाली के नये रूपों को भी लागू करना होगा। ग्रामीण ऋण की विभिन्न प्रक्रियाओं में बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ही होगा।

घ) कृषि को सक्षम बनाने के लिए उन्हें कुशल और पूर्णतया विकसित कृषि बाजार उपलब्ध कराना बहुत ही

आवश्यक है क्योंकि इसका उपयोग वे अपने उत्पादों के सड़ने और नष्ट होने जैसे परंपरागत जोखिम को दूर करने, अधिक अच्छा पारिश्रमिक प्राप्त करने, तथा सामग्री की आपूर्ति बिना बाधा के प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश में कृषि विपणन प्रणाली को एकीकृत करने और मज़बूत बनाने की आवश्यकता है। कृषक जिन जोखिमों को ढोते हैं,जैसे-भविष्य की दरें और मानसून की स्थितियां,उन्हें देखते हुए उचित जोखिम नियंत्रण प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है। तदनुसार कृषि में जोखिम प्रबंधन पर एक निश्चित लोकनीति तैयार करने की आवश्यकता है जो अधिक सक्षम और वाणिज्ययोग्य कृषि को बढ़ावा दे सके तथा जो दबाव में रहे कृषकों को राहत दे सके। ग्रामीण आधारभूत संरचना, जिसमें कृषि अनुसंधान और विस्तार, परिवहन, विद्युत, तथा भंडारण गृह सम्मिलित हैं, न सिर्फ भौतिक साधनों की उत्पादकता में वृद्धि करती है बल्कि यह कृषि में चेन प्रबंध तथा मूल्यवर्धन आपूर्ति में सहायता भी करती है।

ङ) आनेवाले वर्षों में कृषि अनुसंधान पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना होगा क्योंकि अब तक जो भी सफलता मिली है वह चयनित फसलों तक ही सीमित रही है। कृषि अनुसंधान प्रणाली को आधुनिक बनाने और उसे मजबूत करने के प्रयासों, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं, को और भी तेज करने की आवश्यकता है। भारत के कृषि विकास में हरित क्रांति मील का पत्थर बन गया है जिसने हमारे देश को खाद्य अपर्याप्तता से आगे ले जाकर खाद्य स्वावलंबी बना दिया है। आज का समय भी एक और हरित क्रांति के लिए पूरी तरह उपयुक्त है जो कृषि क्षेत्र में और अधिक विविधीकरण पर जोर देगा ताकि बाजार के नए अवसरों को हाथ में लिया जा सके।

ऋण का जहां तक संबंध है, जिसमें बैंकिंग प्रणाली का नियामक होने के नाते रिज़र्व बैंक की भूमिका अहम है, रिज़र्व बैंक के प्रयास रहे हैं कि ऋण सुपुर्दगी की रुकावटों को हटाकर कृषि में ऋण प्रवाह को बढ़ाया जाए। रिज़र्व बैंक अपनी ओर से ग्रामीण कोऑपरेटिव ऋण प्रणाली को पुनर्जीवित करने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने और इक्विटी मूल्य पर और पर्याप्त तथा समय पर ऋण की सुपुर्दगी कराना सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। बैंकों और कई राज्य सरकारों के साथ मिलकर रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समेकन के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम को आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपना कर और अधिक व्यापक बनाया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश

भारत और रिज़र्व बैंक पर इस खंड को समाप्त करने के पूर्व मुझे इतना और कहने का मौका दे कि आंध्र प्रदेश ने लोकनीति के लिए एजेंडा में सबसे ऊपर सिंचाई और कृषि को रखते हुए एक दूरदृष्टि वाला नेतृत्व हमें दिया है। आंध्र प्रदेश में कृषि के उभरते हुए महत्व को समझा और एक नीति तैयार की जो भारत के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनायी जा रही है।रिज़र्व बैंक का सहयोग आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बहुत ही घनिष्ठ रहा है।

निष्कर्ष

मुझे इन शब्दों को दोहराते हुए निष्कर्ष निकालने दे कि अगले दो से तीन दशकों के लिए कृषि उत्पादों हेतु वैश्विक मांग बहुत ही उच्च होगी। भारत दोनों ही अर्थात वैश्विक मांग और वैश्विक आपूर्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। कृषि में उत्तरोत्तर अधिक विविधता

आएगी और यह सिर्फ खाद्य फसलों तक ही सीमित नहीं रहेगा । वैज्ञानिक खेती आज भी और भविष्य में भी कुंजी बनी रहेगी। आगे का मार्ग दूर -दूर तक सुगम नहीं है और इस मार्ग पर बढ़ने के लिए सतत प्रयत्न करते रहने सतर्क रहने और समर्पित रहने की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि आपने जो सूचक पाई है उसका लाभ आपको अपने जीवन में निश्चितता और विश्वास के साथ आगे बढ़ने में मिलेगा।

मेरे प्यारे युवा कृषि और बागवानी के स्नातको, आपके आगे एक उज्ज्वल और बहुत ही उज्ज्वल भविष्य है क्योंकि वास्तव में ही पूरा विश्व भारत की ओर ही देख रहा है। आप कड़ी मेहनत करके सोद्देश्य इसका पूरा लाभ उठाएं और साथ ही खुश रहे। यह स्मरण रखें कि अंतिम लक्ष्य आपका कुछ खुश रहना है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए, इसका अंतिम निर्णय आपको स्वयं अपने विवेक से करना है।